वनों के संरक्षण और सुरक्षा तथा पारिस्थितिक और पर्यावरणीय स्थिरता की जरूरत के कारण वनों पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में कहा गया है कि वनों पर अधारित उद्योगों को अपने कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां तक सम्भव हो, अधिमानतः फैक्टरी और कच्चा माल पैदा करने में सक्षम व्यक्तियों के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित करके कच्चा माल पैदा करना चाहिए।

(ग) उद्योगों को वृक्ष लगाने के लिए वन भूमि पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय को वित्तीय सहायता

2361. **श्री अजीत जोगी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को दी जा रही वित्तीय सहायता दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की तुलना में कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं तथा इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के संस्थागत अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान प्रदान करता है जैसे भवन, पुस्तक और पत्रिकायें, उपस्कर और अन्य सुविधायें जो अध्यापन और अनुसंधान की कोटि और स्तर को प्रोन्नत करने के लिए तैयार की गई हैं। आयोग विशेष सहायता की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी अनुदान प्रदान करता है। विश्वविद्यालयों और कालेजों को इस बात पर ध्यान दिये बिना कि ये किन राज्यों से संबंधित हैं इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार अनुदान दिये जाते हैं। सहायता की राशि छात्रों के नामांकन अध्यापकों और अध्यापन विभागों की संख्या और इसके विकास के स्तर पर निर्भर करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों और कालेजों की तुलना में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान देने में, कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है।

मध्य प्रदेश में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई रेल परियोजनाएं

2362. **श्री अजीत जोगी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989-90 में मध्य प्रदेश में रेलवे से संबंधित किसी परियोजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस अवधि के दौरान किसी अन्य राज्य के रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) रेलवे परियोजनाओं का अनुमोदन राज्यवार नहीं करके अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। वर्ष 1989-90 के दौरान योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित रेलवे परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था :

(1) कारवाड़ तथा मदगांव के मध्य नई रेल लाइन।

(2) काण्डला तथा भटिण्डा के मध्य नया ब्राडगेज सम्पर्क तथा निम्नलिखित खण्डों को शामिल करते हुए आगरा-जैसलमेर/बाड़मेर से ब्राड गेज मार्ग का प्रथम चरण।

(i) भिल्दी-सामदारी से गेज परिवर्तन तथा सामदारी-जोधपुर से सामान्तर ब्राड गेज लाइन।

(ii) फुलेरा-जोधपुर का गेज परिवर्तन तथा बीकानेर (लालगढ़) से मेड़ता रोड का मीटर गेज से ब्राड गेज में परिवर्तन।

(iii) भिल्दी-विरामगाम से गेज परिवर्तन/नई लाइन

(iv) सवाई माधोपुर-जयपुर मीटर गेज का परिवर्तन तथा जयपुर से फुलेरा तक समानान्तर ब्राड गेज लाइन।

कान्हा और बान्धवगढ़ राष्ट्रीय पार्क को केन्द्रीय सहायता

2363. **श्री अजीत जोगी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में कान्हा और बान्धवगढ़ राष्ट्रीय पार्कों को बांध परियोजना और ऐसी अन्य योजनाओं के अधीन कितनी सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस पर समय-समय पर निगरानी रखेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत निम्नलिखित राशि प्रदान की गई:

	(लाख रुपयों में)
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	83.58
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	22.67

इन राष्ट्रीय उद्यानों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी उचित सहायता दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय उद्यानों को दी गई धनराशि के उपयोग की निगरानी करती है और उनके प्रबन्ध में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को सहायता भी देती है।

Taloja unit of Bharat Electronics Limited

2364. DR. BAPU KALDATE: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1412 given in the Rajya Sabha on the 22nd May, 1990 and state:

(a) what are the details of the performance review on the basis of which Government concluded that the Taloja Unit of Bharat Electronics Limited could be viable without raising its existing production capacity;

(b) whether the BEL management's proposal for expansion with an additional investment of Rs. 20 crore, the implementation of which the unit would have an additional turnover to the extent of Rs. 80 crore, was not accepted by Government;

(c) if so, what are the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to reconsider the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) to (d) Bharat Electronics had mooted a proposal in March 1988 to expand the capacity of the Taloja unit from 1 million glass